SHRI ANNATH KUMAR : Mr. Chairman, Sir this does not arise from the main question, yet I want to inform the hon. Member that North-east is a priority area. I will be more than willing to sit with the hon. member and discuss with him about tourism development in Nagaland.

SHRI DRUPAD BORGOHAIN : Mr. Chairman, Sir, I think the money allotted for the development of tourism in Assam is very, very little. Assam is very rich in Natural beauty that comprises of green forests, blue hills, beautiful rivers, rare wild animals, birds, etc. Moreover, it is rich in historical monuments of the Ahoms, Kachari, Chutia and other kingdoms in Kachar district, Sibsagar district, Jorhat district and many other districts. There are some important points like the Majuli island and some other spots also. But these are not being developed properly. There is no proper infrastructure. There are no roads. There are no bungalows so that the tourists can stay there. These difficulties are there. I think the amount which has been announced by the Minister is very little. Will the Minister be kind enough to take pains to develop the tourist industry there properly by providing infrastructure and roads? Will he help the State of Assam? That is my question.

SHRI ANANTH KUMAR : Mr. Chairman, Sir, I entirely agree with the hon. Member. The thing is, total tourism development of the country requires an allocation of Rs. 48,000 crores which should be pooled by public and private industries, by the Central Government and by the various State Governments. The Plan allocation for this year is Rs. 135 crores. In that Rs. 135 crores, this much has been shown against the North-east. ...*(Interruptions)*... I am informing the House about the real fact. The thing is, though there is hardly Rs. 500 crores as Plan allocation for tourism by the Union Government and by all the State Governments, put together, the total foreign exchange earned is Rs. 12,548 crores. This is the third largest foreign exchange earner. Therefore, if there is a concerted effort on getting this Rs. 48,000 crores, at least, in the next Plan period, then, I think, more allocation can be done to Assam also.

Recovery of Outstanding Dues from Sahara Airlines

* 344. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA': Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:—

(a) whether there are some outstanding payments to be made to Government or to the AAI by the Sahara Airlines;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken/proposed to be taken for delay in these payments against Sahara Airlines?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI SHARAD YADAV): (a) and (b) Rs. 2.08 crores is due from M/s Sahara Airlines to the Airports Authority of India.

(c) AAI has withdrawn credit facility granted to the Airlines and has introduced 'cash and carry' system. Existing security deposit has been encashed and adjusted against dues and the security deposit prescribed for Sahara Airlines has also been increased.

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य': सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सहारा एयरलाइंस पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का 2.08 करोड़ रुपया बकाया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह कब से बकाया था और कब से क्रेडिट सुविधा वापस ली गई, बकाया राशि का एडजस्टमेंट कब किया गया और अब उसकी कितनी सेक्योरिटी निर्धारित की गई है ?

श्री शरद यादव: सभापति जी, फरवरी, 2000 का एक महीने का ड्यूज जो सहारा एयरलाइंस द्वारा देना है वह मासिक लगभग 2.25 करोड़ रुपये है और उनकी जो सेक्योरिटी हमारे पास जमा है वह 1.08 करोड़ रुपये है। मैं यह मानता हूं कि एक महीने का जो ड्यूज है वह कोई बड़ी बात नहीं है। हिन्दुस्तान में जो छोटी एयरलाइंस थी वह बंद हो गई हैं और अब केवल दो एयरलाइंस सिविल एविएशन में बची हैं। इन पर जो ड्यूज हैं, उनके बारे में, मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि एक महीने का ड्यूज है। इसके लिए भी हमने सावधानी बरती है कि जो उनकी क्रेडिट है, जो वे मंथली पेमेंट करते हैं, जो हमको ड्यूज मिलता है, हमने उसको बढ़ाकर 2.25 करोड़ रुपये कर दिया है जो कि उनको एक महीने का ड्यूज देना पड़ता है। छोटी एयरलाइंस बड़े पैमाने पर बंद पड़ी हुई हैं। देश में जहाजों की बहुत कमी है और चारों तरफ से, खास करके उत्तर भारत में सिविल एविएशन में बहुत इम्बैलेंस है। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिये यह जो ड्यूज हैं—मिनिस्टरी में आते ही मैंने कहा था कि जितनी भी एयरलाइंस पर जो भी ड्यूज हैं, उनको तत्काल वसूल किया जाए। उसमें हमको सफलता मिली है। यह जो ड्यूज हैं, वह बहुत ज्यादा नहीं हैं और उनको वसूल करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हम यकीन दिलाते हैं कि सरकार को उन ड्यूज को वसूल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और यह कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है।

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य' : श्रीमन् मैंने अपने प्रश्न में सरकार की नीयत पर कोई प्रश्न नहीं उठाया है लेकिन मंत्री जी ने बार-बार सफाई दी कि ड्यूज माफ करने की, कम करने की या बढ़ाने की सरकार की कोई नीयत नहीं है। मैं नहीं समझ पाया कि यह प्रश्न कहां से उठ गया जिसका माननीय मंत्री जी ने इतने विस्तार से उत्तर दिया। जो मूल प्रश्न था, उसका उत्तर बहुत साधारण शब्दों में दिया जा सकता था। अब मंत्री जी ने कहा है कि एक करोड़ से ऊपर का जो

क्रेडिट पेमेंट है, वह बढ़ाकर सवा दो करोड़ कर दिया है और कम्पनी का बकाया जो मंत्री जी ने बताया है वह 2.8 करोड़ है। जब 2.8 करोड़ हो गया तो मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से किया गया क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आता है, वह यह है कि प्रश्न उपस्थित होने के उपरांत यह सारी प्रक्रिया शुरु की गयी है। एक तो मैं इस संबंध में जानकारी चाहता हूं। दूसरा, जो दूसरी एयरलाइंस हैं, क्या उनका किसी प्रकार का बकाया और क्रेडिट बढ़ाया गया है या उनका क्रेडिट सिस्टम नहीं बढ़ाया गया है, उनका सिस्टम ठीक है ?

श्री शरद यादव: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, नीयत का सवाल नहीं है, बात साफ-साफ रखने का सवाल है। मैंने साफ-साफ बात रखी है और नीयत अगर खराब न हो तो देश की यह हालत न हो। जो चीज़ है, जिस पर उन्होंने सवाल पूछा है, उसके लिए जरूरी है कि मैं अपनी नीयत को भी साफ करके बता दूं।

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य': उसमें किसी को संदेह नहीं है।

श्री शरद यादव: आपको संदेह नहीं होगा पर देश भर को संदेह हो सकता है। उनकी इच्छा रहती है कि सरकार सारी बात साफ-साफ बताए। सभापति जी, यह ड्यूज़ एक महीने के हैं। कुछ कम्पनियां बंद हो गयी हैं जैसे गुजरात एयरवेज़ है। ऐसी कितनी ही कम्पनियां हैं। उनका नाम लूंगा तो सदन का समय नष्ट होगा। वह सब ठप्प हो गयी हैं। टर्बोप्रॉप पूरी तरह से वायबल नहीं है, उसमें हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। प्राइवेट कम्पनियों में जैट एयरवेज़ और सहारा इंडिया हैं। एक-आध और छोटी-मोटी है। इस तरह से घिसट-घिसटकर यह एयरलाइंस चल रही हैं। ...(**व्यवधान**)... लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा है।

श्री नरेन्द्र मोहन: क्या इंडियन एयरलाइंस भी घिसट-घिसटकर चल रही है ?

श्री शरद यादव: वह भी इसी तरह से चल रही है। निश्चित तौर पर उसको कभी बजट से पैसा नहीं मिलता है। आप लोग प्रश्न जरूर पूछते हैं लेकिन हमको कोई मदद नहीं करता है। ...(**व्यवधान**)... आप बजट में कुछ प्रावधान कराइए तो हम लोग जोर-शोर से प्रयास करेंगे।

श्री नरेन्द्र मोहन: मान्यवर, क्या आपने इंडियन एयरलाइंस के लिए पैसा मांगा है ?

श्री शरद यादव: काफी मांगा है। आप जानते हैं कि हम मांगने में बहुत मजबूत हैं । हम लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमें बजट से पैसा नहीं मिल रहा है । ...(**व्यवधान**)...

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य' : मांगने में मजबूत रहिए और वसूलने में भी मजबूत रहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादव: महोदय, इस संबंध में इन्हीं के नहीं, बाकी जिस पर भी डयूज़ हैं, हमारी बाकायदा कोशिश है कि जो जनता का पैसा है—खास करके हमारी एयरलाइंस पैसे के मामले में काफी दिक्कत में है और हमको पैसा वसूल करने में ज्यादा आनन्द आता है। इसलिए पैसा पक्के तौर पर वसूल कर लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रामगोपाल यादव: श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने साफ-साफ सारी स्थिति बतायी। मैं यह जानना चाहता हूं कि सहारा एयरलाइंस के अलावा जो अन्य छोटी या बड़ी प्राइवेट कम्पनियां हैं, वह चल रही हैं या बंद पड़ी हैं और उन पर कितना-कितना बकाया है।

श्री शरद यादव: यह बहुत लम्बा है । ...(**व्यवधान**)... कुल मिला करके 32 करोड़ रुपया जो डिफ्रेंट कम्पनीज हैं उनसे लेना है। अगर आप डिटेल्स चाहें तो बतला सकता हूँ।

प्रो. रामगोपाल यादव: हां, डिटेल्स बतला दीजिए।

श्री रामदास अग्रवाल: दो-चार कम्पनी के नाम बतला दीजिए।

श्री शरद यादव: जेट एयरवेज के पास चार करोड़ 72 लाख रुपया है। सहारा का तो आपको बतला ही दिया है। ब्लू डॉट एविएशन जिसमें 15 लाख रुपए है। इंडियन एयरवेज में 22 लाख रुपया है, ई.सी.पी. एयरलाइन्स में चार लाख रुपया है। यू.पी. एयरवेज पर 13.70 लाख रुपया है। सबसे ज्यादा ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के पास है और वह है 18 करोड़ 28 लाख रुपया। जगसन के पास 55 लाख रुपया है। अब इस तरह से कुल मिलाकर के जितनी एयरलाइंस हैं मैंने बतला दिया कि टोटल 32 करोड़ रुपया है। उसकी डिटेल्स हम माननीय सदस्य को भेज देंगे।

श्री सभापति : आप टेबिल ऑफ दी हाउस पर रख दीजिए।

श्री शरद यादव: ठीक है, सर।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता : माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि अभी दो करोड़ आठ लाख रुपया सहारा का बकाया है। अगर यह डिफाल्ट में है तो अलग बात है और अगर यह रनिंग एकाउंट में है तो दूसरी बात है। महोदय, डिफाल्ट में और रनिंग में बड़ा फर्क है। आपने कहा कि दो करोड़ 25 लाख रुपए मंथली चार्जेज वह लोग पे करते हैं और दो करोड़ 8 लाख रुपया उनका बाकी है। तो यह जो बकाया है वह डिफाल्ट में है या रनिंग एकाउंट में है ? तो इस चीज में बड़ा फर्क है। जो ईस्ट-वेस्ट का 18 करोड़ 28 लाख रुपया है वह डिफाल्ट में है मान्यवर। यह रनिंग एकाउंट में नहीं है। एक किस्म से इस एयरलाइंस के लिए जैसे कि सरकार ने, खुद मंत्री महोदय ने कहा कि छोटी एयरलाइंस है और हम चाहते हैं कि एयरलाइंस सर्वाइव करें और कम्पीटीशन दें। तो इस चीज को क्लेरिफाई किया जाए ताकि इस एयरलाइंस के साथ जस्टिफिकेशन हो सके।

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, यह खुद व्यापारी हैं और इस मामले में बड़े एक्सपर्ट हैं। तो हम तो अर्थशास्त्री हैं नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि यह रनिंग एकाउंट का है। ईस्ट वेस्ट के लिए कोर्ट में केस चल रहा है और उनकी पूरी सम्पत्ति जब्त कर ली है, यही हमारे हाथ में है। जो आपने पहला सवाल पूछा वह मैंने बतला दिया कि वह रनिंग एकाउंट का है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

SOME HON'BLE MEMBERS: Sir, there are yet five minutes for the Question Hour to be over.

MR. CHAIRMAN: Yes, you are right. My watch is showing a different time and the watch fixed in the House is showing and different time.

श्री सुरेश कलमाडी: ईस्ट वेस्ट का जो सवाल है वह तो अभी राइट आफ हुआ है और एयरलाइंस का राइट आफ नहीं होना चाहिए, इसलिए तो यह सवाल है। जेट एयरलाइंस और सहारा का एक महीने में उनका कितना ड्यूज होता है ? आप एडवांस डिपोजिट क्यों नहीं लेते ? यह ड्यूज की सिचुएशन का सामना करने के लिए एडवांस डिपोजिट लीजिए। दूसरे, हमारा सवाल है कि जो सहारा एयरलाइंस है इसकी एक न्यूज पेपर कटिंग थी उसमें यह है कि लीज एयर क्राफ्ट जो फंड से लिया है उसका भी ड्यूज है। यह भी एक न्यूज आइटम था। Is the Government aware of this fact that they owe a big amount for the aircraft they have imported for running it in the country? When you gave permission to Sahara and Jet Airways, they have a social commitment to fly in the North-East. Is this commitment being kept by them?

श्री शरद यादव: जो बाहर से पैसा ला रहे हैं, इसके बारे में आपने पूछा है, इस सवाल से इसका कोई वास्ता नहीं है और जो दूसरे सवाल आपने पूछे, फिर से पूछिए, हमको सुनाई नहीं दिया।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Austerity Measures

*345. DR. M.N. DAS : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are concerned with concrete austerity measures in the perspective of heavy fiscal and revenue deficit in the country;